<u>इस्पात समाचार</u>
<u>29 अप्रैल से 5 मई, 2017</u>

<u>जेएसडब्ल्यू द्वारा पॉस्को साईट पर एक मेगा स्टील मिल स्थापित करने की संभावना</u>

सज्जन जिंदल के नेतृत्व में जेएसडब्ल्यू ने आज कहा कि वह ओड़ीशा में एक 10 एमटीपीए क्षमता वाली ग्रीनफील्ड स्टील मिल की स्थापना कर सकता है, विशेषकर पॉस्को प्लांट के लिए पहले चुने गये लोकेशन में । जेएसडब्ल्यू प्रमुख सज्जन जिंदल ने ओड़ीशा के मुख्य सचिव ए पी पाढ़ी के साथ आज शाम को हुई बैठक के बाद यह कहा । ''हम ओड़ीशा में 10 एमटीपीए स्टील मिल की स्थापना करने में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने इस मामले में मुख्य सचिव के साथ चर्चा की है'' जिंदल ने संवाददाताओं को कहा । यह पूछे जानेपर कि क्या कंपनी की नजर पॉस्को परियोजना के लिए पूर्व में पारादीप के करीब अधिग्रहीत जमीन पर है, जिंदल ने कहा ''पॉस्को की साइट संभावनाओं में से एक है। हम भिन्न स्थानों पर लोकेशनों की जॉच कर रहे हैं, जिसमें से एक पारादीप के करीब है ।''

पिछले वर्ष, मुख्यमंत्री के साथ एक बिजनेश मीट में बंगलुरू में बैठक के बाद जिंदल ने ओड़ीशा में एक मेगा स्टील प्लांट की स्थापना करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। राज्य सरकार के स्रोतों ने कहा कि 10 एमटीपीए स्टील मिल और एक 900 मेवा क्षमता वाले पावर प्लांट की स्थापना के लिए कंपनी द्वारा रु 50,000 करोड़ का निवेश करने की संभावना है ।

स्रोत : बिजनेश स्टैंडर्ड, 29 अप्रैल, 2017

<u>सेल वित्त वर्ष 18 में लाल में रह सकता है</u>

इस्पात की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद भी सरकार द्वारा संचालित इस्पात निर्माता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्ष 2017-18 में लाल में रह सकता है, ऐसा संसदीय स्थायी समिति ने महसूस किया है । समिति का अनुमान, तथापि, किसी विस्तृत वर्किंग से समर्थित नहीं है । सेल ने लगातार सात तिमाहियों में हानि होने की सूचना दी है। सेल को वर्ष 2017-18 के दौरान रु 4,211 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज करने की संभावना है, ऐसा पैनल ने अवलोकन किया है । कंपनी रु 64,155 करोड़ का राजस्व इस वित्त वर्ष में अर्जित करने का लक्ष्य बना रही है। इस्पात की कीमतों में गिरावट ने सेल को टॉप लाइन के नीचे बताया है- पिछले तीन वर्षों में वर्ष 2014-15 में रु 53,470 करोड़ से 2015-16 में रु 43,934 करोड़ तक तथा वर्ष 2016-17 के प्रथम 9 महीनों में रु 31,330 करोड़ । इस्पातनिर्माता की कठिनाइयों में शामिल करते हुए भारतीय बाजार चीन, जापान एवं कोरिया से सस्ते आयात से पट गया था, इससे पहले कि सरकार फरवरी 2016 में न्यूनतम आयात मूल्य लागू करने के लिए कदम उठाये। बाद में, कुछ उत्पादों पर एण्टी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी । इस बीच, सेल ने वर्ष 2015-16 में अपने 70,000 ऑड गैर-एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों का बोनस आधा कर दिया था । अध्यक्ष, पी के सिंह ने समिति को सूचित किया कि फर्म का वित्तीय कार्यनिष्पादन दिसम्बर तक 9 महीनों में सुधरा है, जिसमें शुद्ध बिक्री 14.9 प्रतिशतबढ़कर रु 31,330 करोड़ हो गई और व्याज, कर, मूल्यह्रास एवं शोधन (Ebidta) पूर्व आय रु 2,115 करोड़ सुधर कर रु 529 करोड़ हो गयी । शुद्ध हानि इस अवधि में रु 2,062 करोड़ रही । इस अवधि में बिक्री योग्य

इस्पात का उत्पादन एवं बिक्री दोनों पिछले वित्त वर्ष में उसी अवधि के ऊपर 16 प्रतिशतबढ़कर क्रमश: 10.2 मिट तथा 9.7 मिट हो गए हैं।

स्रोत : फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 1 मई, 2017

<u>टाटा स्टील यूके ने स्पेशलिटी स्टील बिज की बिक्री पूरी की</u>

टाटा स्टील यूके ने मंगलवार को घोषित किया कि इसने अपने स्पेशिलिटी स्टील बिजनेश को लिबर्टी हाउस समूह की 100 मिलियन पाउण्ड में बिक्री पूरी की । संघर्ष कर रहे इस्पात निर्माता ने कहा कि बिक्री में शामिल है कई दक्षिण यार्कशायर आधारित परिसंपत्तियॉ, इलेक्ट्रिक आर्क स्टीलवर्क्स तथा बार मिल ब्रिंसवर्थ में । इसके अलावा, यह बोल्टन एवं वेडनेसबरी, यूके तथा सुझोऊ एवं झिआन, चीन में सेवा केन्द्रों को कवर करती है, ऐसा कंपनी ने एक बयान में कहा । स्पेशिलिटी स्टील बिजनेश ने सीधे लगभग 1,700 लोगों का नियोजन किया है, जो एयरोस्पेश, ऑटोमोटिव एवं आयल एवं गैस उद्योगों के लिए स्टील बनाते हैं । टाटा स्टील यूके सीईओ बिमलेन्द्र झा ने कहा कि विगत दो वर्षों में टाटा स्टील ने स्पेशिलिटी स्टील डिविजन में एक कायाकल्प योजना हाथ में ली थी । इसमें शामिल है अत्याधुनिक वैकुम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेश में निवेश, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजनेश के पास स्थिर भविष्य है, उन्होंने बताया । कंपनी ने कहा कि इसने हाल में अपने कर्मचारियों के साथ अपने विस्तृत यूके बिजनेश में घटते हुए जोखिम के प्रस्ताव पर परामर्श किया है। ब्रिटिश स्टील पेंशन स्कीम ट्रस्टीज तथा पेंशन रेगुलेटर के साथ चर्चा भी आने वाले महीनों में अपने यूके पेंशन योजना के लिए स्ट्रक्चरल समाचार विकसित करने के लिए भी चल रही है ।

स्रोत : फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 3 मई, 2017

<u>सेल की योजना है वित्त वर्ष 18 में इस्पात का निर्यात बढ़ाकर दुगुना 1.6 मिट करना</u>

वर्ष 2016-17 में निर्यात में पिछले वित्त वर्ष के ऊपर तीन गुना वृद्धि के साथ सरकार संचालित स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में उसका आउटवर्ड शिपमेण्ट बढ़कर 1.6 मिलियन टन हो जायेगा, जो कि अन्दाजन इसके कुल उत्पादन का 10 प्रतिशतहै । कंपनी पारंपरिक बाजारों का लक्ष्य रखेगी जैसे बंगलादेश, नेपाल, थाईलैंड तथा श्रीलंका - दक्षिण कोरिया तथा मलेशिया एवं ईयू के देश जैसे इटली तथा स्पेन आदि के अलावा । सेल आम तौर पर बिलेट, प्लेट्स, स्लैब, एचआर क्वायल तथा स्टेनलेस स्टील जैसे उत्पादों का निर्यात करता है । इसने वर्ष 2016-17 में 7.2 लाख टन स्टील का निर्यात किया । घरेलू बाजार में मांग में कम वृद्धि के सामने घरेलू इस्पात निर्माताओं के लिए कुछ समय से निर्यात प्राथमिकता लिस्ट में रहा है, खासकर उस समय जब उत्पादन बढ़ोत्तरी पर था । सेल ने बिक्री में वित्त वर्ष 17 में 8 प्रतिशतकी बढ़ोत्तरी 13.14 मिट पर दर्ज की, जो अबतक का इसका सर्वोच्च है । मार्च में भी इसकी बिक्री ने अबतक का सर्वोत्तम मासिक ऑकड़ा 1.57 मिट दर्ज किया हे ।

स्रोत : फाइनेंसियल एक्सप्रेस 3, मई, 2017

<u>भूषण स्टील के ऋणदाताओं ने इसकी ऋण रीकास्ट याजना अस्वीकार कर दी</u>

लेनदारों के एक कंसोर्टियम ने भूषण स्टील के रु 46,000 करोड़ ऋण रीवैम्प योजना को ''अस्वीकार्य'' के रूप में अस्वीकार कर दिया तथा माथ को पुन: करने का निर्देश दिया, क्योंकि चालू योजना लेनदारों के विरुद्ध है, इसके बावजूद कि कंपनी की संभावना उज्जवल है, ऐसा मामले के जानकारी तीन लोगों ने कहा । बैंक मॉग कर रहे हैं कि कंपनी इस तथ्य से सहमत हो कि यह अपने प्रारंभिक योजना की अपेक्षा अधिक ऋण का पुन:भुगतान करने में सक्षम होगी, उन लोगों ने कहा जो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे । बढ़ती हुई इस्पात की कीमतें कंपनी को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाएँगी तथा सर्विस ऋण की इसकी क्षमता में सुधार करेगी, उन्होंने बताया । कंपनी, जिसने रु 46,000 करोड़ बैंकों से ऋण लिया है, ने कहा कि इसके ऋण का सिर्फ 52 प्रतिशतही सस्टेन करने योग्य हैं और शेष तथा कथित एस4ए यानी स्कीम ऑफ सस्टेनेबुल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ट एसेट्स के अधीन इक्विटी में बदली जा सकती है एस4ए नॉर्म सुझाव देता है कि बैंक कंपनी के प्रदर्शित नगद प्रवाह पर आधारित ऋण को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं तथा ऋण के सस्टेनेबल अंश स्टैंडर्ड ऋण के रूप में रख सकते हैं तथा शेष को ''बैड लोन'' के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और उनके लिए प्रावधान कर सकते हैं ।

स्रोत : इकोनामिक टाइम्स, 3 मई, 2017

<u>आयरन ओर का भविष्य उन्नतिशील है</u>

आयरन ओर की कीमतें पिछले सप्ताह भर स्थिर रहीं, परन्तु इसका भावी बाजार अच्छा है, कीमतें फिर से बढ़नी तय है । कीमत में गिरावट को भलीप्रकार से दस्तावेजी कर लिया गया है क्योंकि बेंचमार्क 62 प्रतिशतफॉइन ने फरवरी 21 को $94.86 प्रति टन की ऊँचाई को छू लिया था । उसके बाद 30 प्रतिशतसे अधिक की गिरावट हुई, 19 अप्रैल को $61.60 पर कीमतें सबसे नीचे आने से पहले । चूँकि कीमतें तेजी से गिर रही थीं, कीमतों को मध्यम $60 के रेंज में समर्थन मिल गया था, जो कि पिछली रात $68 प्रति टन पर बन्द हुआ । और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ और खुशखबरी आने वाली है, मंगलवार को मैन्यू0 पीएमआई ऑकड़ों के बावजूद, जिसने विश्लेषकों की भविष्यवाणी को झुठला दिया । आयरन ओर फ्यूचर फिर से ऊपर बढ़ रहा है 4.6 प्रतिशतऊपर तथा चढ़ता ही जा रहा है ।

स्रोत : इकोनॉमिक टाइम्स, 3 मई, 2017

<u>चायनीज स्टील फ्यूचर बढ़ा</u>

चायनीज स्टील फ्यूचर मंगलवार को प्राय: एक महीने में अपने सर्वोच्च पर पहुँच गया , जिसे रीस्टॉकिंग मॉग द्वारा समर्थन किया गया, एक लम्बी छुट्टी वाले सप्ताहांत के बाद । यह अभी भी अस्पष्ट है कि क्या चायनीज स्टील की मॉग के लिए दृष्टिकोण अप्रैल की अपेक्षा मई में उज्जवल होगा ।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स, 3 मई, 2017

<u>घरेलू इस्पात निर्माता सरकारी सोर्सिंग में वरीयता पायेंगे</u>

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने बुधवार को राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को इस्पात के घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए अनुमोदित कर दिया है । इसने सरकारी निविदाओं में घरेलू रूप से उत्पादित स्टील के लिए एक

वरीयता नीति भी अनुमोदित की है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति की खास बात वर्ष 2030 तक इस्पात निर्माण क्षमता के 300 मिलियन टन लक्ष्य को हासिल करना है । इसमें शामिल होगा वर्ष 2030-31 तक रु 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश। लक्ष्य है प्रति व्यक्ति इस्पात खपत का स्तर वर्ष 2030 तक 160 किग्रा तक बढ़ाना , जो कि अभी लगभग 60 किग्रा के स्तर पर है। इस नीति का लक्ष्य है -निजी निर्माताओं, एमएसएमई स्टील उत्पादकों तथा सीपीएसई को नीतिगत समर्थन तथा मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में आत्म-निर्भरता हासिल करना। इसका लक्ष्य प्रतियोगी स्टील मैन्यू0 क्षमता को विकसित करना, लागत किफायती उत्पादन तथा आयरन ओर, कोकिंग कोयला तथा प्राकृतिक गैस की बेहतर घरेलू उपलब्धता भी है । कच्चे माल की विदेशी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण में निवेश करना तथा घरेलू इस्पात की मॉग को बढ़ाना भी इस्पात नीति के एजेण्डा में है । इस्पात मंत्री चौधरी विरेन्द्र सिंह ने फरवरी में बिजनेश लाइन को कहा था ''सरकारी निविदाओं में उन ग्रेडों के लिए घरेलू उत्पादित स्टील का प्रयोग करना अनिवार्य बनाने का प्रावधान हम लाने की ओर नजरें गड़ाये हुए हैं, जो भारत में उपलब्ध हैं । ठेकेदार स्टील के उन ग्रेडों का आयात कर सकते हैं, जो कि देश में वांछित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं ।

स्रोत : बिजनेश लाइन, 4 मई, 2017

<u>घरेलू स्टील के लिए पुश स्थानीय कंपनियों को मदद नहीं कर सकता</u>

ईटी इंटेलीजेंस ग्रुप : समस्त सरकारी परियोजनाओं के लिए घरेलू इस्पात का प्रयोग अनिवार्य बनाने के मंत्रिमण्डल के निर्णय से रक्षा, परमाणु एवं पावर अप्लीकेशन में प्रयुक्त मूल्य वर्द्धित इस्पात के उत्पादों में बढ़ोत्तरी का लक्ष्य है, जो कि सामान्य इस्पात के उत्पादों से दो-तीन गुना मँहगा है। तथापि, अल्प से मध्यम समय में, यह घरेलू स्टील कंपनियों के लिए कोई खास लाभ नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि सरकारी परियोजनाओं में प्रयुक्त आयातित स्टील सीमित है । मूल्य-वर्द्धित स्टील में, नीति का लक्ष्य है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय और उसके द्वारा आयात का विकल्प तैयार करना और वास्तविक वृद्धि मध्यम एवं दीर्घकाल में आ सकती है, ऐसा एच शिवराम कृष्णन, निदेशक (वाणिज्य), एस्सार स्टील बीएसई 0.41% भारत ने कहा, जिसके पास एक उत्पाद बास्केट है जिसमें मूल्य वर्द्धित स्टील का 50% है । इस्पात मंत्रालय के ऑकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 17 में घरेलू इस्पात की खपत थी 84 मिट । इसमें सिर्फ 6 मिट का आयात किया गया था। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयात को लगभग 5 मिट फ्लैट उत्पादों- जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स में होता है तथा 1 मिट लम्बे उत्पादों में विभक्त कर दिया जाय। इस 1 मिट में से 0.6 मिट का प्रयोग रीयल इस्टेट में हुआ था तथा सिर्फ 0.4 मिट संरचना में प्रयोग हुआ था- खासकर सरकारी परियोजनाओं में । इसप्रकार, आयातित स्टील का अंश, जिसके स्थान पर मंत्रिमण्डल के हाल के निर्णय के अनुसार घरेलू स्टील का प्रयोग किया जायेगा, वह वर्तमान कुल मॉग का सिर्फ 1% है। वित्त वर्ष 17 में, भारतीय इस्पात उत्पादक सरकार द्वारा न्यूनतम इस्पात आयात मूल्य लगाये जाने से लाभान्वित हुए हैं। इसने सिर्फ आयात पर अंकुश नहीं लगाया, बल्कि भारतीय उत्पादकों को निर्यात शुरू करने में भी मदद की है । अत:, इसके बावजूद भी कि खपत सिर्फ 1% बढ़ी है, उत्पादन 10% बढ़ा है तथा बढ़े हुए उत्पादन का निर्यात किया गया था । परन्तु बढ़ते हुए रुपये के कारण निर्यात कम लाभजनक हो गया है, जो घरेलू बाजार में अपने भाग के लिए अधिक प्रतिद्वंदिता करेगा। बढ़ते हुए रुपये ने भारतीय बाजारों को विदेशी प्लेयरों के लिए अधिक आकर्षक बनाया है, क्योंकि न्यूनतम आयात मूल्य, जिसे सरकार द्वारा लागू किया गया है, वह डॉलर में है ।

स्रोत : दि इकोनॉमिक टाइम्स, 5 मई, 2017

<u>नई इस्पात नीति की सफलता के लिए क्रियान्वयन प्रमुख है: उद्योग प्रमुख</u>

चुनी हुई सरकारी परियोजनाओं में घरेलू इस्पात की खरीद को अनिवार्य बनाये जाने के सरकार के निर्णय से मॉग बहाल होंगी तथा इस्पात कंपनियों को अधिक जरूरी इम्पेटस प्रदान करेगी, जो ऋण के बोझ तले दबी हुई हैं । इस्पात नीति ऐसे समय में आई है जब सरकार ने इस वित्त वर्ष में संरचना परियोजनाओं में रु 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। तथापि, नीति में विभिन्न प्रावधानों का क्रियान्वयन चिन्ता का विषय बना हुआ है । केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को अनुमोदित किया है, जो चाहती है कि सरकारी निविदाओं की परियोजनाओं में भारत में बने इस्पात के प्रयोग की शर्तें शामिल करके घरेलू इस्पात की खपत को बढ़ावा मिले । रवि उप्पल, प्रबंध निदेशक एवं ग्रुप सीईओ, जिंदल स्टील एण्ड पावर ने कहा कि जबकि नीति ने आपूर्ति एवं मॉग दोनों तरफ की चिंताओं का बेहतर समाधान किया है- प्रमुख चुनौती इसके क्रियान्वयन में मौजूद है। सरकार को दो वर्किंग कार्य दल स्थापित करने चाहिए - एक बड़ी संरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए तथा दूसरा यह निश्चित करने के लिए कि आयरन ओर, कोकिंग एवं थर्मल कोयला जैसे कच्चे माल प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध हों, उन्होंने कहा । जयन्त आचार्य, निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन) जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा कि घरेलू इस्पात की खरीद की अनिवार्यता सही दिशानिर्देशों तथा उचित दस्तावेजों के जरिये क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जैसा कि यूएस, चीन, जापान एवं अन्य देशों में किया गया है। टी वी नरेन्द्रन, प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील ने कहा कि कंपनी नीति के क्रियान्वयन तथा इस्पात खपत क्षेत्रों के भावी वृद्धि की ओर नजरें गड़ाये हुए है, जबकि यह आपूर्ति संबंधी मामलों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता तथा लॉजिस्टिक अड़चनों के निराकरण हेतु सरकार के साथ नीति के लक्ष्य को साकार करने के लिए काम करती है।

स्रोत : बिजनेश लाईन, 5 मई, 2017

<u>उद्योग को मिलेगा रु 40,000 करोड़ का बढ़ावा</u>

देश में उत्पादित आयरन एवं स्टील के लिए कीमत प्रेफरेंश हेतु मंत्रिमण्डल का निर्णय उद्योग को लगभग रु 40,000 करोड़ सहायता प्रति वर्ष देने जा रहा है, ऐसा केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कहा । मंत्रिमण्डल के निर्णय के एक दिन बाद संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा ''संरचना व्यय के लिए बजट किये गये रु 4 लाख करोड़ का लगभग 10 प्रतिशत घरेलू मूल्य प्रेफरेंश के जरिये दिया जायेगा । यह लगभग रु 40,000 करोड़ इस वर्ष के लिए आता है । मंत्री महोदय ने कहा कि 15 प्रतिशत मूल्य प्रेफरेंश के प्रावधान के अतिरिक्त, सरकारी निविदाओं के लिए बोली लगाते समय, स्टील क्षेत्र को बेहतर क्वालिटी के घरेलू कोयला सुनिश्चित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जायेगी । उन्होंने कहा ''धुले घरेलू कोयले के द्वारा आयातित कोकिंग कोयले का विकल्प कोयले के आयात पर व्यय होने वाली कुल विदेशी मुद्रा का लगभग एक चौथाई की बचत करने जा रहा है।'' इस्पात सचिव अरुणा शर्मा ने कहा कि सरकार अब कोकिंग कोयले की खदानों की नीलामी कर रही है, जो घरेलू इस्पात निर्माण उद्योग के लिए लाभकारी होगा । वाशरी की स्थापना तथा आयातित कोयले के बदले देश में उत्पादित कोयले का उपयोग करना वाणिज्यिक रूप से बुद्धिमानी होगी तथा करेंसी एवं मूल्य के उतार-चढ़ाव के जोखिम पर होगी, उन्होंने कहा ।

स्रोत : बिजनेश लाइन, 5 मई, 2017